(ख) से (घ) सरकारने काला-आजार की समस्या से युद्ध स्तर पर निपटने का निर्णय लिया है तथा विभिन्न उपचारी उपायों के समयबद्ध कार्यान्वियन के लिए एक कार्य-योजना तैयार की गई है । इस योजना में केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच विभिन्न जिम्मेदारियां निश्चित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

केन्द्रीय सरकार

1. वैक्टर नियंत्रण ऑपरेशन के लिए डी० डी० टी० 50% डब्ल्यु डी की की पर्याप्त मात्रा में खरीद एवं आपूर्ति करना ।

2. काला आजार के ऐसे रोगियों के उपचार के लिए, जो प्रथम उपचार के लिए, जो प्रथम उपचार औषध अर्थात् सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं । पैंटामिडाइन आइसोथायोनेट के इंजेक्शनों की पर्याप्त मात्रा में खरीद एवं आपूर्ति करना ।

3. काला आजार के रोगियों के उपचार के लिए देश में विनिर्मित प्रथम उपचार औषध सोडियम स्टिबोग्लुकोनेट की खरीद और आपूर्ति ।

बिहार सरकार

1. काला आजार के रोगियों का शुरू में पता लगाना तथा उपचार करना एवं उपयुक्त अनुवर्तन ।

2. विभिन्न स्तरों पर सुस्पष्ट दायित्वों और जिम्मेदारियों सहित विशेष रूप से काला आजार के लिए पर्याप्त आधार-भूत ढांचा तैनात करना ।

3. कार्यकलापों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अनुवर्तन सहित प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार ।

4. प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति सहित पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधायें ।

5. कड़ी सहयोगी और सतत निगरानी और मूल्यांकन के अंतर्गत कार्यक्रम के अनुसार डी डी टी के छिडकाय कार्य की व्यवस्था ।

6. वेक्टर तथा परजीवी दोनों की नियमित मॉनिटरिंग तथा निगरानी ।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने रुपया मुद्रा, विपूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत आय तितपैंटामिडाइन आइसोथायनेट की खरीद के लिए स्वास्थ्य संगठन से सहायता मांगी । युनिसेफ ने भी हिबार सरकार को सूचना, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए 15.55 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की है ।

Dowry-Deaths

544. KUMARI ALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state-

(a) the number of dowry-deaths took place during the past six months; and

(b) what effective steps are being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) A statement showing available figures of dowry-death cases registered during the past six months is enclosed. (*See* below)

(b) The registration, investigation, detection and prevention of crimes including those involving dowry deaths is the responsibility of the State Governments/Union Territories. However, the Government of India have initiated a number of measures to check such crimes. The Dowry Prohibition Act, 1961 was amended in 1984 and 1986 to make the law more stringent. The Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872 were amended to deal effectively with dowry death cases.

A number of schemes are being implemented by the Government as well as through women's voluntary organisations to make women economically independent and aware of their rights. Mass media campaigns against the social evil of dowry through the programmes of electronic media are also being organised.

Instructions have been issued to the State Governments/Union Territory Administrations to effectively enforce legislation, relating to crimes against women which include crimes relating to dowry deaths.

Statement

The Number of Cases Registered as 'Dowry Deaths, during past six months of 1991 *(From 1st January to 30th June* 1991)

Sl. No.	State/UT	Nos.	Fig. upto
	STATES:		
1	Andhra Pradesh	185	
2	Arunachal Pradesh	Nil	
3	Assam	9	
4	Bihar	120	
5	Goa	Nil	
6	Gujarat	49	Except May
7	Haryana	86	
8	Himachal Pradesh	13	
9	Jammu & Kashmir	Nil	
10	Karnataka	113	
11	Kerala	2	
12	Madhya Pradesh	198	
13	Maharashtra	344	
14	Manipur	Nil	
15	Meghalaya	Nil	
16	Mizoram	Nil	
17	Nagaland	Nil	
18	Orissa	26	
19	Punjab	45	
20	Rajasthan	36	March
21	Sikkim	NIL	

Sl. No.	State/UT	Nos. Fig. upto
22	Tamil Nadu	55
23	Tripura	2
24	Uttar Pradesh	786
25	West Bengal	237
	UNION TERRITORIES	
1	A & I lands	Nil
2	Chandigarh	Nil
3	Dadra & Nagar Haveli	Nil
4	Daman & Diu	Nil
5	Delhi	68
6	Lakshadweep	Nil
7	Pondicherry	4

NOTE: The figures are based on monthly crime statistics and may be treated as provisional.

Atrocities on Minorities

545. KUMARI ALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an increase in the incidents of atrocities on the minorities in the different part of the country;

(b) if so, what are the details thereof and the areas where such incidents have taken place recently; and

(c) what are the steps being taken by Government to prevent such incidents?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The registration investigation detection and prevention of crime is the responsibility of the State Governments/Union Territory Administrations. Details of atrocities are not compiled by the Central agencies.

अल्पसंख्यकों का संहार

546. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या विवाद के संदर्भ में घटी ताजी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा अल्पसंख्यकों के संहार के खतरे के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख)